सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-269 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, मंगलवार 03 जून , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

सावधान

कोविड का आंकड़ा 100 के पार, राजस्थान में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा

एक दिन में मिले 15 नए मरीज

जयपुर। जयपुर। राजस्थान में सोमवार को कोविड के 15 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, ये मामले जयपुर, जोधपुर, चूरू और उदयपुर जिलों से आए हैं। सोमवार को जयपुर से सर्वाधिक 10 संक्रमित मिले हैं, जिनमें 5 महिलाएं (उम्र 23 से 51 वर्ष) और 5 पुरुष (उम्र 47 से 79 वर्ष) शामिल हैं। जोधपुर से 3 मरीज (दो महिलाएं और एक पुरुष) संक्रमित पाए गए। उदयपुर में एक 27 वर्षीय पुरुष और एक 15 वर्षीय किशोरी संक्रमित पाई गईं। चूरू से एक 31 वर्षीय पुरुष में संक्रमण की पुष्टि हुई।

जयपुर के मारूधर, जेके लोन, एसएमएस, साकेत और राजस्थान हॉस्पिटल में एक-एक मरीज भर्ती हैं। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 3 मरीज और एम्स जोधपुर में 8 मरीज उपचाराधीन हैं। वर्ष 2025 में अब तक कुल 113 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। एक मरीज की इस वर्ष मौत हो चुकी है।

अब तक के जिलेवार मामले इस प्रकार हैं-

जयपुर-63

उदयपुर-14
जोधपुर-11
बालोतरा-2
अजमेर-2
बीकानेर-6
डूंगरपुर-1
चित्तौड़गढ़-1
राजसमंद-1
सवाई माधोपुर-1
सीकर-1
दौसा-2
डीडवाना-5
फलौदी-1
चूरू-1
अन्य (एपमी)-1

राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक का निधन

कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव सहित विभिन्न सेवाओं के अधिकारी हुए अंत्येष्टी में शामिल

नई दिल्ली/जयपुर । राजस्थान कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आलोक का सोमवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से आलोक दिल्ली में ईलाज चल रहा था। उनके निधन के उपरांत दिल्ली स्थित निवास स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं अन्य विशिष्ट सेवाओं के अधिकारियों सहित राज्य सरकार के दिल्ली स्थित राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल और प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने स्वर्गीय आलोक के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किया।

राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर, ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव और नई दिल्ली में राजस्थान सरकार के मुख्य आवासीय आयुक्त सुधांश पंत, आई. ए. एस. अखिल अरोड़ा, आनंद कुमार, भास्कर सावंत, अपर्णा अरोड़ा, सहित बहुतायत संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों सहित अन्य विशिष्ट लोगों ने लोधी रोड स्थित शवदाह गृह पहुंचकर स्व. आलोक की अंत्येष्टी में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार में पदस्थापित आई.ए.एस. अधिकारी तन्मय कुमार, नरेश पाल गंगवार, रोली सिंह, राज्य के पूर्व मंत्री युनुस खान और सेवानिवृत अधिकारियों सुनील अरोड़ा, श्रीमत पांडेय इत्यादि ने भी उनकी देह पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना व्यक्त की।

उल्लेखनीय है कि स्व. आलोक वर्तमान में उर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा दिल्ली में प्रमुख आवासीय आयुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके अतिरिक्त आलोक ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों सहित सहित राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं।

बीकानेर हाउस में मंगलवार को होगा श्रद्धांजली सभा का आयोजन

स्वर्गीय श्री आलोक को श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में सांय 6 बजे से 7 बजे तक एक श्रद्धांजली सभा का आयोजन रखा गया है।

डेढ़ साल में खाद्य सुरक्षा योजना से 19.90 लाख के काटे नाम, 6 लाख लोगों को जोड़ने की गुंजाइश

खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ लेने वाले लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं

उदयपुर। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में बेझा लाभ लेने वाले लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। वजह ये कि प्रदेश में योजना की सीलिंग सीमा 4.46 करोड़ है, जबकि 4.39 करोड़ नाम जुड़े हुए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में शहरी क्षेत्र के लिए 53 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 69.09 प्रतिशत की सीलिंग निर्धारित की है।

ऐसे में जहां 6 लाख नए लोगों के ही नाम जोडने की गुंजाइश है, जबकि 14 लाख लोग कतार में है।

ऐसे में अपात्र लोगों के नाम चुन चुनकर हटाए जा रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में योजना से 19.90 लाख नाम हटाए गए।

31 मई थी गिव अप अभियान की अंतिम तिथि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों को खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत अपात्र लोगों को योजना से हटने के लिए 31 मई तक का समय दिया था।

योजना से बाहर नहीं होने पर 1 जून से अब तक लिए गए मुफ्त खाद्यान्न की वसूली शुरू कर जी गई है।

मई 2024 से अप्रेल 2025 तक

पांच जिले जहां सबसे ज्यादा नाम हटाए

जयपुर -136500
नागौर - 121135
उदयपुर- 84960
बाड़मेर - 82987
बांसवाड़ा - 82947

पांच जिले जहां सबसे कम नाम हटाए गए

सवाईमाधोपुर - 41246
कोटा - 40327
धौलपुर - 33373
सिरोही - 32842
अलवर - 31984

राजस्थान में पुराने विधानसभा भवन को लेकर छिड़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

जयपुर। जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल (पुरानी विधानसभा) को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के 17 अप्रैल 2025 के फैसले पर रोक लगाने या यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया।

राज्य सरकार ने कोर्ट में दिया ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है, जिस पर विस्तृत सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने तर्क दिया कि याचिका पर सुनवाई तब होनी चाहिए, जब राज्य अपना जवाब दाखिल करे।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोई कदम नहीं उठाएगी। इस आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना कर दिया।

शाही परिवार की ओर से दी गई ये दलील

वहीं, शाही परिवार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि 1949 के समझौते के तहत टाउन हॉल को केवल सरकारी कार्यों के लिए सौंपा गया था। चूंकि विधानसभा अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है, इसका हेरिटेज म्यूजियम या व्यावसायिक

उपयोग करना समझौते का उल्लंघन है।

वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि यह विवाद 1949 के पूर्व-संविधानकालीन समझौते से जुड़ा है, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत टाउन हॉल समेत कुछ संपत्तियां सरकारी उपयोग के लिए दी गई थीं। 2022 में गहलोत सरकार के म्यूजियम बनाने के फैसले के बाद शाही परिवार ने आपत्ति जताई। 2014 से 2022 तक कई नोटिस और शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। शाही परिवार ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर संपत्ति पर कब्जा, रोक और मुआवजे की मांग की। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 363 का हवाला देकर मुकदमा खारिज करने की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ठुकरा दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि ऐसे समझौतों पर दीवानी अदालतों का अधिकार क्षेत्र नहीं है, हालांकि उसने माना कि समझौते के तहत संपत्ति का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट करेगा गहराई से जांच

शाही परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि अनुच्छेद 363 की व्याख्या सीमित होनी चाहिए और यह उनके संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 21, 300) को रद्द नहीं कर सकता, खासकर 1971 के 26वें संविधान संशोधन के बाद, जब शासकों की मान्यता खत्म कर उन्हें सामान्य नागरिक माना गया।

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की गहराई से जांच करेगा कि क्या अनुच्छेद 363 पुराने समझौतों पर लागू होता है और क्या शाही परिवार के संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

सांसद हनुमान बेनीवाल की मांग पर मोदी के मंत्री का एक्शन, भजनलाल सरकार से मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान के सरिस्का और नाहरगढ़ सेंचुरी क्षेत्रों में अवैध कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की मांग पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से इन अभ्यारणों में हो रही अनियमितताओं पर व डिटेल रिपोर्ट तलब की है।

सांसद बेनीवाल ने लोकसभा के बजट सत्र में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना कर होटल मालिकों और खनन संचालकों को फायदा पहुंचाने के लिए अभ्यारणों के नक्शे बदलने के गंभीर आरोप लगाए थे।

इस मुद्दे को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जवाब के साथ साझा किया है।

जंगलो में हो रहे खेल को किया उजागर

राजस्थान के अलवर में स्थित सरिस्का और जयपुर स्थित नाहरगढ़ अभयारण्य क्षेत्रो का नक्शा बदलकर होटल मालिकों, माइंस संचालकों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में जो खेल शुरू किया गया, उसके संदर्भ में मैंने बजट सत्र के समय लोक सभा में मुद्दा उठाते हुए वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण की मांग उठाई थी, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के बावजूद इन अभ्यारणों के इको सेंसेटिव जॉन में कमर्शियल गतिविधियाँ संचालित हो रही है लेकिन राजस्थान की सरकार और जिम्मेदार अधिकारी केवल नोटिस देकर इतिश्री कर लेते है।

सत्ताधारी नेताओं की जान सुरक्षित नहीं-डोटासरा

जयपुर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मंडावर गांव

में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा की अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। सुबह करीब 7 बजे, जब मेवाड़ा खेत से घर लौट रहे थे, हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें झालावाड़ के श्री राजेंद्र अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मंडावर पुलिस के अनुसार, हमले के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस घटना पर भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और यह हत्या इसका स्पष्ट उदाहरण है।

BJP नेता की हत्या पर भड़के डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण झालावाड़ में भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा जी की दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या है। इस घटना ने भाजपा सरकार की सुरक्षा को लेकर किये गए तमाम झूठे दावों की पोल खोल दी है।

राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण झालावाड़ में भाजपा नेता सुरेंद्र मेवाड़ा जी की दिनदहाड़े हुई निर्मम हत्या है। इस घटना ने भाजपा सरकार की सुरक्षा को लेकर किये गए तमाम झूठे दावों की पोल खोल दी है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण

उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस दल की सरकार राज्य में शासित है, उसी पार्टी के नेता की सरेआम हत्या कर दी जाती है और अपराधी बेखौफ होकर भाग जाते हैं। इससे बड़ा कानून व्यवस्था का मजाक और क्या हो सकता है? भाजपा ने सत्ता में आने से पहले 'कठोर कानून व्यवस्था' और 'सुशासन' का दावा किया था, लेकिन मेवाड़ा जी की हत्या दिखाती है कि भाजपा के वादे महज़ जुमले बनकर रह गए हैं। सवाल ये है कि जब प्रदेश में सत्ता पार्टी के नेताओं की जान ही सुरक्षित नहीं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? मेवाड़ा परिवार के प्रति मेरी संवेदना है।

राजस्थान के इन 8 जिलों में खुलेगा जिला एवं सेशन न्यायालय, सरकार ने अधिसूचना की जारी

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। इनमें फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूंबर शामिल हैं। अब राजस्थान की सभी ग्राम पंचायत में होगा ऐसा बड़ा काम, कैबिनेट मंत्री ने दी खुशखबरी दरअसल, बाड़मेर जिला पहले बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायालय के अधीन था, अब बालोतरा के नवीन राजस्व जिला बनने के बाद स्वतंत्र जिला एवं सेशन न्यायालय प्राप्त करेगा।

सरकार ने की अधिसूचना जारी

बता दें, राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे न्याय तक पहुंच को आसान बनाने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन नए न्यायालयों में जिला एवं सेशन जज, अतिरिक्त जिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारी नियुक्त होंगे। साथ ही, इनके संचालन के लिए भवन, कर्मचारी और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

दूरदराज के लोगों को मिलेगा फायदा

यह पहल ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी। स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाओं की उपलब्धता से छोटे-मोटे विवादों के लिए लोगों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि नए न्यायालयों से न केवल न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी न्याय आसानी से उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि सरकार ने इन न्यायालयों के लिए बजट और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक ये न्यायालय कार्यशील हो जाएंगे।

राजस्थान में जहां पानी की सबसे बड़ी झील, वहां पानी के संकट से पलायन कर रहे लोग

जयपुर। जयपुर से मात्र 80 किलोमीटर दूर राजस्थान के सांभर झील कस्बे में पानी की समस्या ने अब विकराल रूप ले लिया है। कभी खारे पानी की सबसे बड़ी झील के लिए प्रसिद्ध यह इलाका अब प्यास, पलायन और प्रशासनिक उदासीनता की त्रासदी का पर्याय बन गया है।

पुश्तैनी हवेलियां बिकने के कगार पर

सांभर के कई मोहल्लों में पानी की किल्लत इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अपनी पुश्तैनी हवेलियां और लाखों के मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर हैं। चारभुजा मंदिर की गली, जोशियों की गली, लक्ष्मीनारायण मंदिर की गली और चौधरियों की गली जैसे क्षेत्रों में हालात बद से बदतर हैं। स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से पलायन का फैसला लिया है, जिसकी गवाही गलियों में लगे

'मकान बिकाऊ' और 'पानी के लिए पलायन' के पोस्टर दे रहे हैं।

बता दें, सांभर के वार्ड 22 और 23 सबसे अधिक प्रभावित हैं, जहां जलदाय विभाग की ओर से 72 से 96 घंटों में केवल 25-30 मिनट की जलापूर्ति होती है। कई घरों में तो एक बाल्टी पानी भी नसीब नहीं होता। स्थानीय निवासी जगदीश बोहरा बताते हैं कि पानी का कोई निश्चित समय नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं।

वहीं, व्यवसायी पराग पोद्दार, जिनकी 250 साल पुरानी हवेली है और ज्वैलर ललित सोनी जैसे लोग भी पानी की कमी के चलते अपने घर छोड़ने पर विचार कर रहे हैं।

नहीं सुन रहे विभाग के अधिकारी

स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार-बार समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभाग के अधिकारी फोन पर उचित जवाब तक नहीं देते।

यहां के निवासियों का मानना है कि यह पानी की नहीं, बल्कि प्रशासन की इच्छाशक्ति की कमी है। कुछ मोहल्लों में नियमित जलापूर्ति हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्र प्यासे हैं।

जलदाय विभाग का बिल हर महीने समय पर आता है, लेकिन नल सूखे रहते हैं।

कई गलियों में टैंकरों की पहुंच भी संभव नहीं है, जिसके चलते लोग आधा किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। सांभर में पानी की टंकी की स्वीकृति सालों पहले मिल चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। सरकारी फाइलों में योजनाएं मंजूर होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वही ढाक के तीन पात है।

स्थानीय विधायक पर भेदभाव का आरोप

स्थानीय लोगों ने फुलेरा विधायक विद्याधर चौधरी ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि पूर्व विधायक निर्मल कुमावत ने अमृत योजना के तहत टेंडर होने की बात कही, लेकिन तकनीकी अड़चनों का हवाला दिया।

गौरतलब है कि सांभर को सरकार पर्यटन हब बनाने की बात करती है, लेकिन वहां के लोग जीने के लिए कस्बा छोड़ रहे हैं। पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते लोग, सूखे नल और खाली घड़े अब इस कस्बे की पहचान बन गए हैं। यह राजधानी के नजदीक होने के बावजूद एक ऐसी जल-त्रासदी है, जहां विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।

बदलते दौर में अनिवार्यता बनती साइकिल

आज के ज़माने में लोग घंटों साइकिल चालकर इससे सेहत और वातावरण को पहुंचने वाले फायदों के बारे में जागरुकता फैलाते हैं। हालांकि यूरोप, डेनमार्क, नीदरलैंड इत्यादि दुनिया के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं, जहां साइकिल के जरिये ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 के बीच काफी अच्छा चला लेकिन उसके बाद समय बदलता गया और साइकिल का चलन भी कम होता गया। बीते कुछ वर्षों में पर्यावण की महता और साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ को देखते हुए लोग साइकिल की ओर आकर्षित हुए हैं और यही कारण है कि अब केवल भारत ही नहीं बल्कि जापान, इंग्लैंड सहित कई विकसित देशों में भी साइकिलों का उपयोग बढ़ रहा है।

(लेखक- - योगेश कुमार गोयल)

(विश्व साइकिल दिवस (3 जून) पर विशेष)

एक समय ऐसा था, जब लोग मीलों दूर का सफर भी पैदल अथवा बैलगाड़ियों के माध्यम से कई-कई दिनों में पूरा किया करते थे। साइकिल के आविष्कार ने लोगों की दुनिया ही बदल डाली, जिसने लोगों के लिए मीलों दूर का सफर भी आसान बना दिया था। कुछ दशक पूर्व तो बहुत से छात्र स्कूल तक पहुंचने के लिए भी मीलों दूर का सफर साइकिल से ही तय किया करते थे। हालांकि वह ऐसा दौर था, जब साइकिल को आमतौर पर निर्धनता का प्रतीक समझा जाता था और साइकिल को गरीब तथा मध्यम वर्ग के यातायात का ही अहम हिस्सा माना जाता था। तब खासकर मजदूर वर्ग के लोग, दूध वाले, स्कूल जाने वाले छात्र इत्यादि ही साइकिल पर दिखते थे। साइकिल की कीमत तब ज्यादा नहीं होती थी और प्रायः एक ही जैसी साइकिलें बाजार में मिलती थी लेकिन समय के साथ बदलती तकनीक के दौर में साइकिलें भी हाईटैक होती गई और आज बाजार में कुछ हजार से लेकर लाखों रुपये तक की साइकिलें उपलब्ध हैं।

समय के साथ साइकिल की उपयोगिता और महत्व भी बदलता गया है और आज के आधुनिक दौर में साइकिलें अधिकांशतः व्यायाम अथवा शारीरिक फिटनेस के तौर पर प्रयोग की जाती हैं। आज के ज़माने में लोग घंटों साइकिल चालकर इससे सेहत और वातावरण को पहुंचने वाले फायदों के बारे में जागरुकता फैलाते हैं। हालांकि यूरोप, डेनमार्क, नीदरलैंड इत्यादि दुनिया के कई हिस्से आज भी ऐसे हैं, जहां साइकिल के जरिये ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 के बीच काफी अच्छा चला लेकिन उसके बाद समय बदलता गया और साइकिल का चलन भी कम होता गया। बीते कुछ वर्षों में पर्यावण की महता और साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभ को देखते हुए लोग साइकिल की ओर आकर्षित हुए हैं और यही कारण है कि अब केवल भारत ही नहीं बल्कि जापान, इंग्लैंड सहित कई विकसित देशों में भी साइकिलों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत का साइकिल उद्योग आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और भारत साइकिल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।

साइकिल पर्यावरण के लिए यातायात का सबसे उत्तम साधन है क्योंकि इसके उपयोग से डीजल-पैट्रोल का दोहन कम होने के साथ ही प्रदूषण स्तर भी कम होता है, साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने में भी साइकिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साइकिल चलाने से न केवल पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होता है। यही कारण है कि साइकिल की विविधता, मौलिकता और परिवहन के एक व्यापक और सहज साधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 3 जून को 'विश्व साइकिल दिवस' मनाया जाता है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 3 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा साइकिल सवारी से मिलने वाले स्वास्थ्य, पर्यावरण और आवागमन के लिए सबसे सस्ता साधन इत्यादि को देखते हुए की थी। दरअसल साइकिल का महत्व धीरे-धीरे घटता जा रहा था, तकनीक के विकास के साथ ही पैट्रोल-डीजल इत्यादि से चलने वाली गाड़ियों का उपयोग बढ़ने लगा और लोगों ने समय की बचत तथा सुविधा के लिए साइकिल चलाना बेहद कम कर दिया। इसीलिए साइकिल के उपयोग और जरूरत के बारे में बच्चों और अन्य लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व साइकिल दिवस मनाने की जरूरत महसूस की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण सुरक्षा को भी साइकिल चलन को बढ़ावा देने का अहम उद्देश्य माना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साइकिल दिवस मानव प्रगति, उन्नति, स्थिरता, सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति के प्रतीक के रूप मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत को लेकर अमेरिका के मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसजेक सिबिल्स्की ने एक अभियान चलाया था, जिसका समर्थन तुर्कमेनिस्तान और 56 अन्य देशों ने किया था। सिबिल्सकी ने ही साइकिल दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सिबिल्सकी और उनके साथियों द्वारा उसका प्रचार-प्रसार किया गया।

साइकिल यातायात का ऐसा साधन है, जो वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसे चलाने के लिए पैट्रोल, डीजल या सीएनजी जैसे किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। साइकिल चलाने से अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे वजन कम करने से लेकर मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। साइकिल चलाना एक प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज है, जिससे शरीर को चुस्त-दुरूस्त रखने, पतला होने और मांसपेशियों को टोन करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमित साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी भयानक बीमारियों का जोखिम कम होता है और यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के करीब साइकिल चलाता है तो यह उसे तरोताजा रखने के साथ-साथ उच्च रक्तचाप जैसी समस्या को भी दूर रखने में मददगार है। साइकिल चलाने से मूड अच्छा होने में भी मदद मिलती है। कई अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि प्रतिदिन आधा घंटा साइकिल चलाने से ही हम मोटापा, हृदय रोग, मानसिक बीमारी, मधुमेह, गठिया इत्यादि कई बीमारियों से बच सकते हैं। चिकित्सकों के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ घुटनों की समस्या नहीं हो, इसके लिए प्रतिदिन साइकलिंग करनी चाहिए, जिससे जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। साइकिल चलाने से न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है, ब्रेन पावर बढ़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि साइकिल चलाने से 15 से 20 प्रतिशत अधिक दिमाग सक्रिय होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकलिंग करने से इम्यून सिस्टम तो अच्छा होता ही है, साथ ही इम्यून सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे विभिन्न बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। साइकलिंग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, जिससे रत्तीभर भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। आधा घंटा साइकलिंग करने से बॉडी फिट रहती है, शरीर पर चर्बी नहीं आती, पाचन क्रिया ठीक रहती है, हृदय और फेफड़े मजबूत बनते हैं और कई जानलेवा बीमारियां दूर रहती हैं। चूंकि साइकिल स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है, इसीलिए दुनियाभर में साइकिल के चलन को बढ़ावा देने का सीधा सा अर्थ है वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना क्योंकि साइकलिंग में स्वाभाविक शून्य उत्सर्जन मान होता है, इसीलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कमी में बड़ा योगदान देती है।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

संपादकीय

पढ़ने की उम्र में जुर्म

हिसार में सहपाठी द्वारा प्रतिशोध में कक्षा दस के एक छात्र की गोली मारकर की गई हत्या ने हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोरा है। एक साल पहले स्कूल में डेस्क पर बैठने को लेकर विवाद की खुंदक आरोपी छात्र अपने दिमाग में पालता-पोसता रहा। फिर एक दिन सहपाठी को सुबह मिलने के बहाने बुलाया और अपने दादा के हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेहद दुखद है और हर मां-बाप के लिये बेहद चिंता का विषय कि उनके बच्चे का सहपाठी भी इतना खूंखार हो सकता है। हमारे जिस समाज की प्यार, सामंजस्य व सहयोग के लिये मिसाल दी जाती थी, उसमें ये किशोर आखिर ऐसा भयानक कदम कैसे उठा रहे हैं? जिस उम्र में किशोरों को पढ़ना-लिखना था, उस समय में वे हिंसक गतिविधियों में क्यों लिप्त हो रहे हैं? दोषी तो आरोपी छात्र के अभिभावक भी हैं कि जिन्होंने घातक हथियार को लापरवाही से घर में छोड़ा, जिससे आरोपी ने हत्या को अंजाम दिया। बताते हैं कि आरोपी छात्र के दादा सेना से सेवानिवृत्त हैं और एक बैंक में सुरक्षा गार्ड हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता था और अपने परिवार को हमेशा के लिये रोता-बिलखता छोड़ गया। एक समय अमेरिका व यूरोप में ऐसी घटनाएं सुनने में आती थी। अब ये किशोर अपराध हमारे दरवाजों पर भी दस्तक देने लगे हैं। समाज में व्याप्त नकारात्मकता व हिंसक प्रवृत्ति का किशोरों द्वारा अनुकरण करना हमारे समाज के लिये खतरे की घंटी ही है। बीते मार्च में दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक छात्र की ऐसी ही निर्मम हत्या हुई थी। वजीराबाद की घटना में एक नौवीं के छात्र का अपहरण करके उसके परिजनों से दस लाख की फिरौती मांगी गई थी। छात्र की हत्या के बाद जांच में पता चला कि उसके अपहरण व हत्या में तीन किशोर संलिप्त थे। आए दिन स्कूल-कालेज विवाद में हिंसक घटनाएं हमें परेशान करती हैं। यदि कम उम्र के बच्चों व किशोरों में बढ़ती हिंसक प्रतिशोध की प्रवृत्ति पर लगाम न लगी तो डर लगता है कि आने वाले समय में हमारे समाज का स्वरूप कैसे होगा। सवाल यह है कि आखिर किशोरों में आपराधिक प्रवृत्तियां क्यों पनप रही हैं। आखिर उन्हें मां-बाप का संघर्ष क्यों नहीं दिखायी देता कि वे कैसे उन्हें पाल-पोस व पढ़ा-लिखा रहे हैं? समाज विचार करे कि वे कौन से कारक हैं जो बच्चों को आपराधिक प्रवृत्ति का बना रहे हैं। उनके द्वारा ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिये जिम्मेदार प्रवृत्ति का स्रोत क्या है? ऐसे बच्चों में कानून का भय क्यों नहीं है? कभी लगता है कि हमारे जीवन का हिस्सा बने तकनीकी साधन बच्चों के विवेक पर आक्रमण कर रहे हैं। जिससे उनमें सही-गलत की सोच की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म, वेब सीरीज तथा इंटरनेट में व्याप्त आपराधिक कार्यक्रम उन्हें हिंसक बना रहे हैं। जिससे वे बेलगाम सपनों के संजाल में भी फंसते हैं, जिन्हें पूरा करने को वे हिंसक राह पर उतर जाते हैं।

आम आदमी की सवारी है साइकिल

(लेखक- रमेश सर्राफ धमोरा)

(03 जून विश्व साइकिल दिवस पर विशेष)

साइकिल मानव ऊर्जा को गतिशीलता में बदलने के लिए अब तक का सबसे कुशल साधन है। साइकिल का व्यापक रूप से परिवहन, मनोरंजन और खेल के लिए उपयोग किया जाता है साइकिलें उन क्षेत्रों में लोगों और सामान को ले जाने के लिए आवश्यक हैं जहां कम वाहन उपलब्ध हैं। साइकिल से वायु प्रदूषण को कम करने के साथ पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। ऐसे में विश्व साइकिल दिवस का महत्व समाज के सभी लोगों के बीच साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर साइकिल सवारी को प्रोत्साहित करना है।

3 जून 2018 को पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। तब से दुनिया में प्रतिवर्ष साइकिल दिवस मनाया जाने लगा है। इस बार हम सातवां विश्व साइकिल दिवस मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवहन के सामान्य, सस्ते, विश्वसनीय, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में इसे बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 12 जून 1817 को जर्मनी के मैनहेम में बैरन कार्ल वॉन ड्रैस ने दुनिया की पहली साइकिल पेश की थी। यह लकड़ी से बना था और इसमें पैडल, गियर या जंजीर नहीं थी। उसने खुद को पहले एक पैर से और फिर दूसरे पैर से धकेला। उन्होंने इसे लॉफमाशाइन (जर्मन में चलने वाली मशीन) कहा। अब तो जापान के फुकुकोआ शहर में छात्रों ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो हवा से चलती है।

भारत की आर्थिक तरक्की में साइकिल ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आजादी के बाद से ही साइकिल देश में यातायात व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा रही है। खासतौर पर 1960 से लेकर 1990 तक भारत में ज्यादातर परिवारों के पास साइकिल थी। यह व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन था। गांवों में किसान साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी और दूसरी फसलों को साइकिल से ही ले जाते थे। दूध की सप्लाई गांवों से पास से कस्बाई बाजारों तक साइकिल के जरिये ही होती थी। डाक विभाग का तो पूरा तंत्र ही साइकिल के बूते चलता था। आज भी पोस्टमैन साइकिल से चिट्ठियां बांटते हैं। चीन के बाद आज भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल बनाने वाला देश है।

भारत में भी विकसित की जा रही ज्यादातर आधारभूत आधुनिक संरचनाएं मोटर-वाहनों को ही सुविधा प्रदान करने के लिए बन रही हैं। साइकिल जैसे पर्यावरण-हितैषी वाहन को नजर अंदाज किया जा रहा है। जबकि शहरी व ग्रामीण परिवहन में भी साइकिल का महत्वपूर्ण स्थान है। खासतौर से कम आय-वर्ग के लोगों के लिए साइकिल उनके जीविकोपार्जन का एक सस्ता, सुलभ और जरूरी साधन है। यह इसलिए भी कि भारत का कम आय-वर्ग के लोग अपनी कमाई से प्रतिदिन सौ-पचास रुपये परिवहन पर खर्च करने में सक्षम नहीं हैं।

बच्चे सबसे पहले साइकिल चलाना ही सीखते है। इसलिये बचपन में हम सभी ने साइकिल चलाई है। पहले के जमाने में जिसके पास साइकिल होती थी वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। गांव के लोग जब कभी शहरों में जाते थे। तब लोगों को साइकिल चलाते हुए देखते थे और फिर वे खुद भी धीरे-धीरे साइकिल चलाना सीख जाते थे। पहले शहरों में किराए पर भी साइकिले मिलती थी।

देश की युवा पीढ़ी को अब साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल ज्यादा अच्छी लगने लगी है। शहरों में मोटरसाइकिल का शौक बढ़ रहा था। गांवों में भी इस मामले में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बावजूद भारत में साइकिल की अहमियत खत्म नहीं हुई है। 1990 के बाद से साइकिलों की बिक्री में बढ़ोतरी आई है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी बिक्री में गिरावट आई है। दरअसल 1990 से पहले जो भूमिका साइकिल की थी। उसकी जगह गांवों में मोटरसाइकिल ने ले ली है। इसके उपरांत भी साइकिल आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं।

देश में लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों में कमाने गए लाखों लोग साइकिल पर 1000-1500 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंचे थे। संकट के समय साइकिल ही उनके घर पहुंचने का एकमात्र साधन बनी थी। लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों के घर पहुंचने का सबसे उपयोगी साधन बनने से लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गयी की साइकिल आज भी आम लोगों का सबसे सस्ता व सुलभ साधन है।

अब तो विभिन्न प्रकार के फीचर से लैस गियर वाली कीमती साइकिले बाजार में आ गई है। पहले लोगों के पास सामान्य साइकिले ही हुआ करती थी। जिनके पीछे एक कैरियर लगा रहता था। जिस पर व्यक्ति अपना सामान रख लेता था व जरूरत पड़ने पर दूसरे व्यक्ति को बैठा लेता था। कई बार तो साइकिल सवार आगे लगे डंडे पर भी अपने साथी को बिठाकर 3-3 लोग साइकिल पर सवारी करते थे। साइकिल से वातावरण में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता था। पेट्रोल डलवाने का झंझट भी नहीं था। साइकिल उठाई पैडल मारे और पहुंच गए अगले स्थान पर। पहले के जमाने में साइकिल के आगे एक छोटी सी लाइट भी लगी रहती थी। जिसका डायनुमा पीछे के टायर से जुड़ा रहता था। साइकिल सवार जितनी तेजी से साइकिल चलाता उतनी ही अधिक लाइट की रोशनी होती थी।

2020 में विश्व साइकिल दिवस के दिन ही भारत की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कम्पनी एटलस बंद हो गयी थी। प्रतिवर्ष 40 लाख साइकिल का उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी व दुनिया की जानी मानी कम्पनी एटलस के बंद होने से साइकिल उद्योग को बड़ा धक्का लगा है। एटलस की फैक्ट्री बंद होने से वहां काम करने वाले करीबन एक हजार लोग बेरोजगार हो गये। एटलस साइकिल कम्पनी की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका कई विदेशी साइकिल निर्माता कंपनियों के साथ गठबंधन था। जिस कारण एटलस कम्पनी की साइकिल दुनिया भर की श्रेष्ठ साइकिलों में शुमार होती थी।

(चिंतन-मनन)

सच्चा मित्र संजीवनी की तरह

हम सभी के परिचित और दोस्त होते हैं। भले ही बचपन के, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या आस-पास कॉलोनी में रहने वाले हों, मित्र तो सभी के होते हैं। सच्चा मित्र बनना और बनाना हर इंसान की इच्छा होती है। लेकिन, सच्चे मित्र बहुत कम मिल पाते हैं। ऐसा मित्र, जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसके साथ अपनी हर बाते शेयर कर सकें। धर्मशास्त्रों में सच्चा मित्र उसे कहा गया है, जो सुख-दुख में साथ दे। ऐसे दोस्त से कभी भी डर नहीं लगता। ये सही रास्ते पर चलने में हमारे मददगार होते हैं। लेकिन, ऐसा दोस्त कौन है? क्या वह जो सिर्फ परिचित है? सच्ची दोस्ती प्रेम, विश्वास व भरोसा, एक-दूसरे का ख्याल रखने और चिंताओं पर ही आधारित होती है। क्या, कभी इस प्रश्न का उत्तर आपने खुद से पूछा है? प्रिय शब्दों से मित्रों की संख्या बढ़ती है और मधुर वाणी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार। हमारे परिचित अनेक हों, किंतु परामर्शदाता ईश्वर एक ही है। ईश्वर ही सच्चा दोस्त है, जो जीवन के हर पल में हमारी परछाई बनकर साथ रहता है। उस पर अपनी आंखें बंद कर, विश्वास व भरोसा करते हैं। जब सुखी या दुखी होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के रूप में उससे बातें करते हैं। जीवन की हर बात उससे साझा करते हैं और फिर खुद को हल्का महसूस करते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत हम ईश्वर से आशीर्वाद लेकर ही करते हुए कहते हैं-हे मेरे मालिक, मुझ पर अपनी छत्र-छाया बनाए रख, मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे सफलता प्रदान कर। कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति में साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है और अलगाव का दोष भी हमें ही देता है। कोई मित्र हमारे यहां खाता-पीता है, किंतु विपत्ति के वक्ति दिखाई नहीं देता। समृद्धि के दिनों में वह हमारा अंतरंग बन कर रौब जमाता है, किंतु दुर्दिन आते ही शत्रु बनकर मुंह फेर लेता है। परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, लेकिन उस पर तुरंत विश्वास मत करो। अपमान, अहंकार और विश्वासघात के कारण मित्रता टूट जाती है। कभी ऐसा भी होता है, जिस दोस्त पर हम सबसे ज्यादा विश्वास व भरोसा करते हैं, वही विश्वासघात करता है और हृदय पर चोट लगने पर मित्रता टूट जाती है।

अगर, हम संकट और दरिद्रता में मित्र का साथ दें तो उसकी समृद्धि और विरासत के साझेदार बन सकते हैं। सच्चा दोस्त जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उससे घर-परिवार व समाज में पहचान बनती है। सच्चा मित्र प्रबल सहायक है। जिसे मिल जाता है, समझो उसे खजाना मिल गया। ऐसे मित्र की कीमत धन से नहीं चुकाई जा सकती। सच्चा मित्र असल में संजीवनी है। इंसान जैसा है, उसका मित्र भी वैसा ही होगा।

विचार मंथन

लेजर हथियारों के साथ लड़ा जाएगा विश्व युद्ध?

(लेखक- सनत जैन)

इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने युद्ध क्षेत्र में लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर दुश्मन के ड्रोन गिराये हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ब्रिगेडियर जनरल ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने हाई पावर लेजर का पहला प्रयोग युद्ध भूमि पर सफलतापूर्वक किया है। एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें लेजर किरणें ड्रोन पर निशाना साधते हुए दिख रही हैं। लेजर किरणों से ड्रोन के पंख में आग लग गई और वह गिरकर नष्ट हो गया। लेजर सिस्टम की इजराइल डिफेंस कंपनी ने इसे विकसित किया है। यह तकनीक प्रकाश किरण (लेजर बीम) के माध्यम से अपने लक्ष्य को तय करती है और लक्ष्य में पहुंचते ही उसे नष्ट कर देती है। इजराइल लेजर को आयरन बीम के साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर इसकी तैनाती कर रहा है। वर्तमान में तीसरे युद्ध की आशंका देखने को मिल रही है। घातक हथियारों से पूरी दुनिया के देश लेस हैं। तीसरा विश्व युद्ध अत्याधुनिक तकनीकी से लड़ा जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, ऑटोमेटिक सिस्टम और घातक हथियारों के साथ होगा। यदि इस प्रकार से तीसरा विश्व युद्ध होगा तो कितना विनाशकारी होगा, इसकी कल्पना मात्र से भय लगता है। पिछले कुछ महीनो में जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में पारंपरिक हथियार ड्रोन के माध्यम से अत्याधिक स्वचालित प्रणाली से जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, वह मानवीय जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। अत्याधुनिक प्रभावशाली घातक हथियार जिस तरह से विनाश कर रहे हैं, उसको देखते हुए आज सारी दुनिया भयाक्रांत है। किस देश ने कौन सी तकनीकी तैयार कर ली है और कौन से हथियार तैयार कर लिए गए हैं, इसकी जानकारी अन्य देशों के पास उपलब्ध नहीं होने से इनसे बचाव करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा है। इसमें दोनों ही देश का भारी विनाश हुआ है। इजराइल आज सारी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इजराइल और फिलीस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध में अभी तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा एक तरह से बर्बाद हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस युद्ध को रोकने में कोई भूमिका अदा नहीं कर पाई हैं। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने जो हमले गाजा पर शुरू किए थे, वे इतने विनाशकारी होंगे इसकी कल्पना भी वर्तमान में करना मुश्किल है। अब लेजर किरणों से यदि विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो भगवान ही मालिक होगा। इसके परिणाम किस तरह के होंगे, यह कहना मुश्किल है। युद्ध के मैदान में अभी तक लाइटरिंग म्युनिशंस ड्रोन लक्ष्य का पता लगाकर हमला करते हैं। मिसाइल रक्षा प्रणालियां एआई आधारित ड्रोन, परमाणु हथियार, रूस की सामरिक परमाणु मिसाइल, उत्तर कोरिया की हाउसांग मिसाइलें, रासायनिक एवं जैविक हथियारों आदि का तृतीय विश्व युद्ध में यदि उपयोग किया गया, तो विनाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस तरह से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका दिखने लगी है, उसको देखते हुए महाभारत काल की भी याद आने लगी है। भगवान कृष्ण के कहने पर कौरवों ने पांच गांव भी पांडवों को नहीं दिए थे। महाभारत का युद्ध हुआ। यह इतना विनाशकारी था कि युद्ध खत्म होने के बाद कौरव और उनकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में पांडव यह युद्ध जीत गए थे। लेकिन किसके ऊपर राज करेंगे यह उन्हें समझ नहीं आया। जिनके ऊपर राज करना था वह महाभारत के युद्ध में नष्ट हो चुके थे। ऐसी स्थिति में पांडवों को भी वानप्रस्थ की ओर जाना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का इजराइल पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अमेरिका भी इजराइल को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के कई महीनो से चल रहे युद्ध को भी रोका नहीं जा सका है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया तनाव देखने को मिल रहा है। चीन नई भूमिका में आ गया है। ऐसी स्थिति में जो दुनिया भर के देशों ने घातक हथियार बनाकर रखे हैं, उनसे कितना बड़ा नुकसान होगा। इसकी कल्पना सहज रूप से नहीं की जा सकती है। दुनिया के सभी देशों में आज एक दूसरे से लड़ने की मानसिकता बनी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध में जो विनाश हुआ था, उसके बाद लोगों ने शांति के पथ की ओर बढ़ाना शुरू किया था। दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध की तरह नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया के देश शांति के साथ मानवीय सभ्यता का विकास कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से वैश्विक व्यापार संधि के बाद जो पूंजीवाद का भयानक रूप सामने देखने को मिल रहा है।

देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, इन तरीकों से रखे अपने को सुरक्षित

नई दिल्ली।

भारत में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहां कोविड के सक्रिय केस की संख्या 1200 के पार हो गई है। कोविड की पहली लहर के दौरान भी सबसे ज े यादा केरल राज े य ही प्रभावित हुआ था। इस बार भी केरल में कोरोना का प्रकोप दिख रहा है। दि ल्ली और महाराष् ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज् यों में इनके सक्रिलय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बाद सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

लोगों में डर का माहौल है। हालांकि अभी यात्रा पर कोई रोक नहीं है। ट्रेन से लेकर, बसों या फ्लाइट से लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं। इसके बाद आपको जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर कैब से ट्रैवल करते हैं, तब आपको मास्क पहनना जरूरी है।

मास्क पहनें- भले ही अभी सरकार के द्वारा ट्रैवल को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, फि र भी आप रेलवे स े टेशन, बस स े टेशन या फिर एयरपोर्ट या किसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास े क जरूर पहनें। इससे आपको कई हद ते क सुरक्षा मिलेगी।

हैंड सैनिटाइजर रखें साथ- अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं,तब आपको हर आधे घंटे में हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है। खासकर कुछ खाने से पहले जरूर सैनि टाइज करें। इससे वायरस को रोकने में मदद मिलेगी।

बंद जगहों पर जाने से बचें- कोविड से बचने का सबसे अच े छा तरीका है कि आप खुली जगहों पर रहें। अगर आप किसी भी बंद जगहों पर या पार्टी में जाते हैं, तब भी कोविड की चपेट में आने का खतरा ज े यादा होता है। कुल मिलाकर आपको खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर आपको बुखार, थकान, गले में खराश और कंजेशन जैसी समस े या हो रही है, तब आपको तुंरत

डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा मास े क का इस्तेमाल करें।

पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने ली कई जानें, लाखों लोग प्रभावित

वायुसेना और असम राइफल्स के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे

नई दिल्ली।

पूर्वोत्तर भारत में बारिश ने तबाही मचाई है। बीते कई दिनों से बारिश और उसके बाद की घटनाओं से जीवन अस्त-व्यस्त है। बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। बता दें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बीते तीन दिनों में भारी बारिश हुई और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच वायुसेना और असम राइफल्स के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल इस बारिश से 5 जून तक राहत नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले कुछ घंटों में तेज बारिश हो सकती है। 4 जून तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं अरुणाचल, असम और मेघालय में भी भारी बारिश की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में स्थिति गंभीर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के बीच उत्तरी सिक्किम में 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे हैं। भूस्खलन की वजह से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। वहीं 29 मई को मुंशीथांग में तीस्ता नदी के पास लापता हुए 8 पर्यटकों का अभी तक पता नहीं चल सका है। असम के 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें लखीमपुर, डिब्रूगढ़, हैलाकांडी, होजई, कामरूप, धेमाजी और कछार जैसे जिलों में करीब 3.6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन से होने वाली मौतों का आंकड़ा रविवार तक 10 तक पहुंच गया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित 155 राहत शिविरों में 55 हजार से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। अरुणाचल प्रदेश बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। राज्य भर में करीब सभी नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है जिसके बाद सीएम पेमा खांडू ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है कि बहुत जरूरी हो तब ही घर से बाहर निकलें। मेघालय में 10 जिले अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। त्रिपुरा में भी 10 हजार से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। इस बीच असम राइफल्स ने वायुसेना के साथ मिलकर 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है और उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई। वहीं रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से बात की।

फंगस एसपर्गिलस जलवायु परिवर्तन के कारण फैल सकता तेजी से

नई दिल्ली।

ताजा शोध में दावा किया गया है कि एक खतरनाक फंगस एसपर्गिलस जलवायु परिवर्तन के कारण पहले से अधिक तेजी से फैल सकता है। बदलती जलवायु न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बन रही है, बल्कि यह इंसान की सेहत पर भी गंभीर असर डाल रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह फंगस इंसान के शरीर को अंदर से खा सकता है और फेफड़ों समेत कई अंगों में गंभीर संक्रमण फैला सकता है। स्टडी के अनुसार, ग्लोबल वॉर्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण यह फंगस अब केवल ट्रॉपिकल इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीन और रूस जैसे ठंडे इलाकों में भी अपनी पकड़ बना सकता है। अनुमान है कि यदि फॉसिल फ्यूल्स का दहन यूं ही जारी रहा, तो एसपर्गिलस से जुड़ी बीमारियों के मामले 16 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो यह फंगस आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की जान का खतरा बन सकता है। स्वास्थ्य प्रणाली को इसके प्रति सतर्क रहने और फंगल इन्फेक्शन की रोकथाम के उपायों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह आपने कोविड-19 महामारी के दौरान देख ही लिया। हाल ही में आई एक स्टडी इन छोटे जीवाणुओं के खतरे के बारे में आगाह कर रही है, लेकिन इस बार बात बैक्टीरिया या वायरस की नहीं, बल्कि फंगस की हो रही है। जी हां, एसपर्गिलस नाम का एक फंगस जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ सकता है, जो आने वाले समय में लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

बीसीआई के अध्यक्ष ने की शर्मिष्ठा की रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग

नई दिल्ली।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने इंस्टाग्राम 'इन्फ्लुएंसर' शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई और निष्पक्ष सुनवाई की मांग की।

कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को एक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हिंदी फिल्म अभिनेता 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चुप हैं। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सदस्य मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया वीडियो वायारल के लिए माफी मांगने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कोलकाता की रहने वाली और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा 22 साल की 'इन्फ्लुएंसर' को शुक्रवार रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। शर्मिष्ठा पनोली को शनिवार को कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मिश्रा ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है कि वह सरकार, जिसने बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था, अब दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाने वाली छात्रा को चुप कराना चाहती है।

बीजेपी ने रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी सरकार पर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए 'युवा हिंदू महिला' को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कानून को चुनिंदा तरीके से लागू करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी के दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस में हलचल, शमशेर सिंह गोगी का तीखा बयान

चंडीगढ़।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 जून को चंडीगढ़ दौरे से पहले हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने संगठनात्मक मुद्दों को लेकर बड़ा बयान देते हुए पार्टी के भीतर की खींचतान पर खुलकर नाराजगी जताई है। गोगी ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में हरियाणा कांग्रेस के संगठन को मज़बूत किया जा रहा है, लेकिन अगर जम्मिेदार पदों पर गलत लोगों को बैठाया गया तो संगठन को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठा दोगे तो दूध थोड़ी बचेगा? उनके इस बयान को कांग्रेस के कुछ नेताओं पर परोक्ष हमला माना जा रहा है। गोगी ने ज़ोर देकर कहा कि जिलाध्यक्ष जैसे पदों पर उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो सच्चे कांग्रेसी हों, न कि वे जो अपने निजी स्वार्थ या रिश्तेदारी को प्राथमिकता दें। उनका यह बयान आगामी संगठनात्मक बैठकों से पहले पार्टी के लिए एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपने साथ हुई अन्यायपूर्ण स्थिति की बात कही थी। गोगी ने कहा, अगर सैलजा को साथ लिया गया होता तो आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं होती। कांग्रेस, कांग्रेस से ही हारी है। गोगी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी याद किया जिसमें उन्होंने पार्टी में स्लीपर सेल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी के विचारों का पूरी तरह समर्थन करते हैं और आशा है कि इस बार संगठन मज़बूती से खड़ा किया जाएगा।

राहुल गांधी के दौरे से पहले ही हरियाणा कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाएं और बयानबाज़ी तेज हो चुकी है। अब 4 जून की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या कोई बड़ा फैसला होता है या फिर यह आंतरिक खींचतान आगे भी यूं ही जारी रहेगी।

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए नई वेबसाइट शुरू करेगी सरकार

वक्फ के संचालन के नियमों को लेकर राज्यों के साथ विचार-विमर्श होगा

नई दिल्ली।

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच केंद्र सरकार इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर तैयारियों में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक के ंद्र सरकार इस समाह वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक नई वेबसाइट शुरू कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार वक्फ के संचालन के नियमों को लेकर जल्दी ही राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई वेबसाइट पर देशभर की वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसमें उनके मुतवल्लियों की संपत्ति भी शामिल होगी। वहीं केंद्र सरकार वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी चर्चा करेगी। बता दें कानून के तहत राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में होंगे और उनमें राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व भी होगा। राज्यों से सलाह और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्ड के लिए नियमों को अधिसूचित कर सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बीते अप्रैल माह में वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसके बाद 5 अप्रैल को इसे

राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके बाद कुछ मुस्लिम संगठनों और सांसदों ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं के विरुद्ध संशोधित वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। बीते माह तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

देश में अवैध रूप से रह रहे हजारों बांग्लादेशियों को वापस भेजा, कार्रवाई जारी

गुजरात, दिल्ली, हरियाणा के बाद अन्य राज्यों में भी शुरु होगा ऑपरेशन

नई दिल्ली।

भारत ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बीते माह इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से देश में अवैध रूप से रह रहे हजारों बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2000 घुसपैठियों को सीमा पार भेजा जा चुका है और यह कार्रवाई जारी है। इस दौरान भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बढ़ने की खबरें भी सामने आई हैं।

मीडिया रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा है।

अधिकारियों ने इससे पहले देश भर में सत्यापन भी शुरू किया है। सूत्रों ने बताया कि बड़ी कार्रवाई के बाद एक्शन से डर से 2000 से ज्यादा घुसपैठिए खुद बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। रिपोर्ट में सरकारी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि यह प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों के दस्तावेजों की जांच कर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस प्रक्रिया में और तेजी आई है। गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई है। जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को वापस भेजा गया है उनमें से करीब आधे गुजरात के हैं। वहीं दिल्ली और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस भेजा गया।

इसके अलावा असम, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस प्रक्रिया में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) भी सहयोग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक असम, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों में प्रक्रिया तेजी से जारी है। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया कि अलग-अलग राज्यों से पकड़े गए घुसपैठियों को भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर पर लाया जा रहा है।

इसके बाद इन्हें बीएसएफ को सौंप दिया जाता है, जो इन्हें अस्थाई शिविरों में रखते हैं। कुछ घंटों की हिरासत के बाद उन्हें सीमा के जरिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है।

राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का निधन

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक

जयपुर।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी और राजस्थान के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक का 58 साल की उम्र में निधन हुआ है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निधन पर शोक जताया है। बताया जा रहा हैं आईएएस आलोक कई दिनों से बीमार थे। उनका सोमवार को दिल्ली में निधन हुआ। आलोक 1993 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1966 को पटना में हुआ था। राज्यपाल बागडे ने उनके आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त कर ईश्वर से पुण्यात्मा को शांति देने और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने शोक व्यक्त कर कहा, ''भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं राज्य के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है।''उन्होंने लिखा, ''प्रभु श्री राम से प्रार्थना है

कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिवार को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'' पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य नेताओं ने भी आईएएस आलोक के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है।

संक्षिप्त समाचार

सिक्किम में आर्मी कैंप पर भूस्खलन, 3 की मौत, 9 जवान लापता

सर्च ऑपरेशन जारी, 1500 से ज्यादा पर्यटक फंसे

गंगटोक(ईएमएस)। पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य में रविवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ। उत्तरी सिक्किम के चट्टन क्षेत्र में स्थित आर्मी कैंप पर हुए भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि भारतीय सेना के नौ जवान अब भी लापता बताए गए हैं। हादसा 01 जून की शाम लगभग 7 बजे हुआ। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। लापता जवानों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव दल युद्धस्तर पर अभियान चला रहे हैं। भूस्खलन इतना तीव्र था कि आसपास के कई घर भी इसकी चपेट में आ गए। सेना और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से मलबे में दबे लोगों को निकालने का कार्य जारी है। उत्तर सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोचन और लाचुंग क्षेत्रों में लगभग 1,500 पर्यटक फंस गए। मंगन जिले के एसपी सोनम देचू भूटिया के अनुसार, लाचेन में 115 और लाचुंग में 1,350 पर्यटक अलग-अलग होटलों और गेस्टहाउसों में ठहरे हुए हैं। राहत की बात यह है कि लाचुंग के लिए सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है, और आज से पर्यटकों की निकासी शुरू की जा रही है।

बीआरओ ने तेज़ी से संभाली स्थिति

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने लाचुंग-चुंगथंग-शिपग्येरे-शंकलांग-डिकचू रोड पर जमा मलबा हटाकर रास्ता साफ किया है। सस्पेंशन ब्रिज पर आई दरारों को भर दिया गया है, जिससे राहत कार्य में तेजी आई है।

यूपी में 40 दिन में 3 टंकियां गिरीं

लखनऊ।

यूपी में जल जीवन मिशन से लोगों को उम्मीद जगी कि अब घर तक पानी आएगा। इंतजार खत्म हुआ, लेकिन टंकियां गिरने से उम्मीद टूटने लगी। सीतापुर में 3 दिन पहले अचानक ढाई लाख लीटर की पानी टंकी तेज धमाके के साथ फट गई। कुछ सेकेंड तक बादल फटने जैसा मंजर दिखा। घरों में 1 फीट तक पानी भर गया। यह पहली बार नहीं है, 40 दिन में यूपी में गिरने वाली यह तीसरी टंकी है। लखीमपुर और कानपुर में इसी तरह से पानी की टंकियां धड़ाम हो गईं। तीनों टंकियों में एक समानता है, सभी जिंक एलम की हैं।

विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग

पटना।

लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लोजपा रामविलास पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान सुरक्षित सीट के बजाए सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों के चयन को लेकर पार्टी मंथन करने में जुटी है। पिछले दिनों लोजपा रामविलास पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों और मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लडऩे का। चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के अगुआई में लड़ेंगे और एनडीए की मजबूती के लिए साथ प्रचार करेंगे।

मई में दो लाख करोड़ वसूला गया जीएसटी

टूटा रिकॉर्ड, पिछले साल से 16 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली।

जीएसटी वसूली में मई महीने में रिकॉर्ड टूट गया है। मई महीने में 2,01,050 करोड़ रुपये जीएसटी वसूली हुई। इस महीने में पिछले साल के मुकाबले 16.4 फीसदी अधिक जीएसटी संग्रह किया गया। इससे पहले अप्रैल महीने में सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये था। यह 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह था। मार्च 2025 में जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा था। वहीं मार्च में सकल जीएसटी संग्रह 9.9 प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। मार्च में घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 8.8 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं से राजस्व 13.56 प्रतिशत बढ़कर 46,919 करोड़ रुपये हो गया।

बिना अनुमति मक्का में प्रवेश नहीं, 2.69 लाख लोगों को हज पर जाने से रोका

- हज नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना होगी कार्रवाई

रियाद (एजेंसी)। सऊदी अरब में हज यात्रा को लेकर इस बार बहुत सख्ती बरती जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना अनुमति कोई भी मक्का में कदम नहीं रख सकता। इस सख्ती के चलते अब तक 2.69 लाख से ज्यादा लोगों मक्का में आने से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की और हज नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने और कार्रवाई की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि हज में भीड़भाड़ के लिए अनाधिकृत यात्रियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल की भीषण गर्मी में मरने वालों में बड़ी संख्या ऐसे ही बिना अनुमति आने वाले थे। फिलहाल, करीब 14 लाख से ज्यादा हज यात्री मक्का पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी लोगों के पहुंचने की संभावना है। सऊदी सरकार के नियमों के मुताबिक बिना अनुमति हज करने वाले व्यक्ति को पांच हजार अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना और निर्वासन जैसे कठोर दंड दिया जा सकता है। रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि 23,000 से ज्यादा सऊदी निवासियों पर हज नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया है, जबकि हज से जुड़ी 400 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

आप किसी गठबंधन में नहीं, बिहार में अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि बिहार में आप अकेले ही दम पर चुनाव लड़ेगी। आप दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद अब पंजाब पर फोकस कर रही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के शीर्ष नेता प्रचार के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। आप के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अनुराग ढांडा ने कहा कि आप किसी गठबंधन में नहीं है। हमारे पास अपनी खुद की ताकत है। हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए था। हम अब किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं। बता दें आप कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए संगठन मजबूत करने पर काम कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पार्टी ने राज्यों को दो कैटेगरी में बांटा है। ए-कैटेगरी में वह राज्य हैं, जहां बड़े टिकट पर मुकाबला है और जहां अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय रहेंगे। इनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और गोवा शामिल है।

पीएम मोदी 6 जून को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का उद्घाटन कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक सेवा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर, पवित्र नगर कटरा और कश्मीर घाटी को सीधे रेलमार्ग से जोड़ेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कटरा स्थित स्टेडियम में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक- कटरा से बारामुला तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पहले यह सेवा 19 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन खराब मौसम की चेतावनी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 7 से 10 मई के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर के कारण इसमें देरी हुई।

बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग

-3 चरणों में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव

पटना(एजेंसी)। (ईएमएस)। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वोटिंग की डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि 2020 का विधानसभा चुनाव 3 फेज में हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार आएगी। हालांकि, अभी तारीख अभी तय नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. आयोग अब हर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को पहचान पत्र देने की तैयारी में है, जिससे वह घर-घर जाक सत्यापन का कार्य कर सकें. बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिससे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें. चुनाव आयोग बिहार चुनाव तक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड शुरू कराने की भी तैयारी में है. इसमें आयोग से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी. सूत्रों की मानें तो बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार दो से तीन चरणों में हो सकते हैं. चुनाव की तारीखें तय करते समय दीवाली और छठ जैसे त्योहार का भी ध्यान रखा जाएगा. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है और चुनाव आयोग की तैयारी इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर

विमानन क्षेत्र में वैल्यू चेन लीडर के रूप में उभरेगा भारत : मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आईएटीए (अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ) के सालाना आम बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र वैश्विक हवाई परिवहन उद्योग में एक प्रमुख इकाई है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र के लिए भारत के पास एक बाजार, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के लिए प्रतिभा और मुक्त एवं सहयोगी नीति मौजूद है। पीएम ने दावा किया कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागर विमानन बाजार है। भारत विश्वस्तरीय हवाई अड्डों में निवेश कर रहा है, हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 162 हुई।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार सभी कदम उठा रही। विमानों की मरम्मत एवं रखरखाव (एमआरओ) एक उभरता हुआ क्षेत्र, भारत को 2030 तक एमआरओ का एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ हमारी यात्रा योजना सिर्फ धरती के शहरों तक ही सीमित नहीं है। आज इंसान अंतरिक्ष उड़ानों और अंतरग्रहीय यात्राओं का व्यवसायीकरण करने और उन्हें नागरिक उड्डयन के लिए खोलने का सपना देख रहा है। यह सच है कि इसमें अभी कुछ समय है, लेकिन यह बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितना बड़ा परिवर्तन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है।

मोदी ने कहा कि भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं भारत के तीन मजबूत स्तंभों का उल्लेख करता हूँ जो इसके लिए आधार हैं- पहला, भारत के पास बाज़ार है। यह बाज़ार सिर्फ उपभोक्ताओं का समूह नहीं है, बल्कि भारत के आकांक्षी समाज का प्रतिबिंब भी है। दूसरा, हमारे पास प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए जनसांख्यिकी और प्रतिभा है। हमारे युवा नए युग के नवोन्मेषक हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सफलताएँ ला रहे हैं। तीसरा, हमारे पास उद्योग के लिए खुली और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र नीति है। इन तीन क्षमताओं के आधार पर हमें भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। हमारी उड़ान योजना की सफलता भारतीय नागरिक उड्डयन का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से अधिक यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा की सुविधा मिली है। कई नागरिकों ने पहली बार हवाई यात्रा की। हमारी एयरलाइंस भी लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि हासिल कर रही हैं।

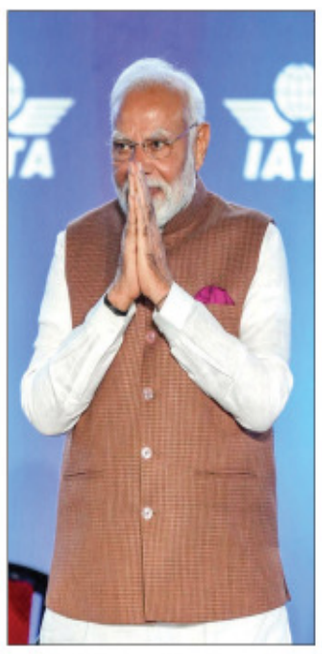

भारत और उसके बाहर 25,000 से अधिक संगठनों ने योग दिवस को लेकर दिखाया उत्साह

नई दिल्ली (एजेंसी)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तारीख करीब आने के साथ ही इसका उत्साह भी खासा बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के प्रमुख उत्सव कार्यक्रम 'योग संगम' को पहले ही भारत और उसके बाहर 25,000 से अधिक संगठनों से असाधारण प्रतिक्रिया मिल चुकी है। जी हां, योग के अब तक के सबसे बड़े और सबसे समावेशी उत्सव के लिए मंच तैयार कर रहा है।

शीर्ष-स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों से लेकर प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों तक, और प्रमुख कॉरपोरेट्स से लेकर प्रभावशाली सरकारी विभागों तक, हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। एकल फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय योग संघ और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संगठन जैसे संगठन उनमें से हैं जिन्होंने पूरे दिल से इसमें भाग लेने का संकल्प लिया है।

उल्लेखनीय शैक्षणिक संस्थानों ने योग संगम की भावना को उत्साह के साथ अपनाया है। आईआईटी कानपुर, आईआईएम मुंबई, एनआईटी कुरुक्षेत्र, आईआईएम बैंगलोर, बीआईटी मेसरा और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने पंजीकरण कराया है, जिससे भारत के सबसे प्रतिष्ठित परिसरों में इस कार्यक्रम की गूंज दिखाई देती है।

यहां तक कि सरकारी विभाग भी उदाहरण पेश कर रहे हैं। गोवा वन भवन के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, अल्टिन्हो ने योग संगम के साथ हाथ मिलाया है - जो पर्यावरण जागरूकता और समग्र कल्याण के साथ योग के संरेखण पर प्रकाश डालता है।

वहीं राज्य स्तर पर, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब संगठनात्मक पंजीकरण में अग्रणी के रूप में उभर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में योग के लिए गहरे समर्थन को दर्शाता है।

मणिपुर में बाढ़, प्रभावित इलाकों से सैकड़ों लोगों का किया रेस्क्यू

-अस्पताल में फंसे मरीजों को निकालने नावों का किया इस्तेमाल

इंफाल (एजेंसी)। 'ऑपरेशन जलराहत-2' के दूसरे दिन भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर में व्यापक बाढ़ बचाव अभियान जारी रखा है। पिछले दो दिनों में बच्चों और बुजुर्गों समेत 1300 से ज्यादा नागरिकों को बचाया गया। मीडिया रिपोर्ट में रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार को 800 लोगों को बचाया गया था और रविवार को इंफाल समेत सबसे ज्यादा प्रभावित इंफाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों से 500 लोगों को बचाकर राहत शिविरों में ले जाया गया।

सेना और असम राइफल्स के जवानों ने वांगखेई, हेइंगंग, लामलोंग, खुरई, जेएनआईएमएस और अहलप जैसे गंभीर रूप से जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को निकाला। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि बचाव कार्यों के लिए सेना के इंजीनियरों की बीएयूटी, इन्फ्लेटेबल नावों से लैस 10 बाढ़ राहत कॉलम्स को तैनात किया गया था। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने थौबल जिले के लिलोंग में अरपती लामखाई के पास टूटी हुई इरिल नदी की सीमा की दीवार की मरम्मत भी की ताकि आगे बाढ़ को रोका जा सके। सरकारी स्वामित्व वाले जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस) और अस्पताल में फंसे मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। राहत क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों को करीब 800 बोतल पीने का पानी और अन्य जरुरी आपूर्ति वितरित की गई।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और असम राइफल्स प्रभावित समुदायों तक पहुंचने और सभी तरह की मदद देने के लिए नागरिक अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करना जारी रखे हुए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा कि इम्फाल और इरिल समेत कई नदियों ने खुरई, हेइंगंग, चेकोन और वांगखेई के कम से कम पांच क्षेत्रों में तटबंधों को तोड़ दिया, जिससे इम्फाल और आसपास के इलाकों के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। इम्फाल पश्चिम जिले में नम्बुल नदी भी रविवार को उफान पर आ गई, जिससे उरीपोक और सामुसांग में बाढ़ आ गई। नगरम में, पूरे दिन बारिश होने से बाढ़ का पानी रहवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर गया।

तुर्किये में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई शांति वार्ता, यूक्रेन के दिए जख्मों को भुला जेलेंस्की को गले लगा पाएंगे पुतिन?

कीव (एजेंसी)। यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधियों ने इस्तांबुल में शांति वार्ता का दूसरा सत्र आयोजित किया। इस दौरान यूक्रेन ने युद्ध विराम और सभी कैदियों की अदला-बदली सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। यह घटना कीव द्वारा यूक्रेनी सीमा से हजारों किलोमीटर दूर स्थित चार रूसी एयरबेसों पर हाई-एंड ड्रोन का उपयोग करके अचानक हमला करने के ठीक एक दिन बाद हुई है। इसे अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशनों में से एक कहा गया। यूक्रेन के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने किया, जबकि रूसी प्रतिनिधियों का नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने किया। रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों में उनके रक्षा, विदेश मामलों और खुफिया सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, साथ ही वार्ता में दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष सलाहकार और उप मंत्री भी शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, तुर्की के अधिकारियों की मेजबानी में दूसरे दौर की वार्ता लगभग एक घंटे तक चली। यह 16 मई को हुई पहली वार्ता के बाद हुई है, जो दो घंटे तक चली और बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला-बदली पर समझौते के साथ संपन्न हुई, लेकिन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

यूक्रेन का ड्रोन हमला

इस तनाव को और बढ़ाते हुए यूक्रेन ने 1 जून को रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कथित तौर पर चार रूसी एयरबेस और 40 युद्धक विमानों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, हमलों में यूक्रेन से 7,000 किलोमीटर से अधिक दूर रूस के आर्कटिक, साइबेरिया और सुदूर पूर्व में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी संसद की सदस्य किरा रुडिक ने कीव द्वारा किए गए ड्रोन ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 0 रूसी जेट विमानों का नष्ट होना कोई संयोग नहीं है। रूस हम पर 500 ड्रोन और मिसाइलें दागता रहता है - यह केवल समय की बात है कि कब उनकी तरफ से चीजें बदलनी शुरू होंगी।

राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पांच जून को, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे उपस्थित

अयोध्या (एजेंसी)। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ तीन जून से होने जा रहा है। यह त्रिदिवसीय धार्मिक अनुष्ठान पांच जून को गंगा दशहरा के पावन पर्व के दिन पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंदिर परिसर में उपस्थित रहेंगे। विशेष बात यह है कि पांच जून को मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, जिससे यह दिन और अधिक पुण्यमय बन गया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चम्पत राय ने सोमवार को यहां पत्रकारों को बताया कि मंदिर के परकोटे में छह देवी-देवताओं के मंदिर शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा और शेषावतार के आठ मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूजन कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से आरंभ होंगे और अंतिम दिन यानी पांच जून को सुबह 11:25 बजे मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा लंदन, अंबेडकर संग्रहालय का किया दौरा

-थिंक-टैंक और भारतीय प्रवासियों के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेगा मुलाकात

लंदन (एजेंसी)। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में लंदन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। यह प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा आतंकवाद को हराने के लिए भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए साझेदार देशों तक पहुंचने के प्रयासों का हिस्सा है।

प्रतिनिधिमंडल ने लंदन स्थित अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया और बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब के नेतृत्व और दूरदर्शिता का स्मरण करते हुए सांसदों के दल ने याद दिलाया कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद का सबसे जघन्य उदाहरण 26 नवंबर 2008 को मुंबई में शुरू हुआ था। यह वह दिन था जब हमने 1949 में बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान को अपनाया था। सांसदों ने सभी प्रकार के आतंकवाद का सामना करने और उसे पराजित करने के संकल्प पर जोर दिया।

दुनियाभर में पाक को बेनकाब कर लौट रहे सर्वदलीय डेलिगेशन से मिलेंगे पीएम मोदी, 9-10 जून को हो सकती है मुलाकात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मिलने की उम्मीद है, जिन्हें पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरूआत के बाद भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत 33 देशों में भेजा गया था। यह बैठक 9 या 10 जून को नई दिल्ली में होने की संभावना है। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, वरिष्ठ राजनीतिक नेता और अनुभवी राजनयिक शामिल हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत की स्थिति पेश करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने का काम सौंपा गया है। सूत्रों के अनुसार, आगामी बैठक में प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री को अपनी यात्रा के दौरान हुए प्रमुख घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे जिसमें उच्च स्तरीय बैठकें, रणनीतिक बातचीत, तथा पहलगाम हमले और भारत के व्यापक आतंकवाद-रोधी प्रयासों के संबंध में विभिन्न देशों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं शामिल होंगी। सरकार ने सात प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे। प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रमुख सांसद द्वारा किया गया।

बांग्लादेश में करेंसी से हटाई शेख मुजीब की तस्वीर, नई करेंसी जारी

-करेंसी में मस्जिद-मंदिर की तस्वीरें, विपक्ष व नागरिक पूछ रहे सवाल

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश बैंक ने नई करेंसी जारी की है जिसमें दशकों से मौजूद राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है, उसकी जगह धार्मिक स्थलों विशेष रूप से मस्जिदों की तस्वीरें छापी गई हैं। करेंसी में मंदिर की तस्वीरें भी लगाई है, लेकिन सवाल एक प्रमुख मस्जिद की तस्वीर को लेकर, जिसे लेकर विपक्ष, बुद्धिजीवी और आम नागरिक सवाल पूछ रहे हैं। क्या यह नया बांग्लादेश है या तालिबानी सोच की वापसी?

1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान से आजादी दिलाने वाले शेख मुजीब बांग्लादेश की पहचान थे। उनके चेहरे वाला नोट सिर्फ करेंसी नहीं था बल्कि एक विचार था, लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद सत्ता में आई नई सरकार का रुख अब इस पहचान को मिटाने में लगा है। सिर्फ करेंसी नहीं कई सरकारी इमारतों, संस्थानों और सड़कों से भी शेख मुजीब से जुड़ी पहचान को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांग्लादेश बैंक ने 9 में से 3 नोटों की नई सीरीज जारी की है। इसमें न किसी नेता का चेहरा है, न राष्ट्रपिता की छवि। करेंसी में मस्जिद बौद्ध विहार, मंदिर और बंगाल अकाल पर आधारित एक प्रसिद्ध चित्र को। हालांकि जहां एक ओर ये विविधता प्रतीत होती है, वहीं मस्जिद की प्रमुखता को लेकर यह आलोचना हो रही है कि धार्मिक एजेंडा को 'राष्ट्रीय प्रतीकों' पर थोपने की कोशिश की जा रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मानवता के खिलाफ अपराधों का केस दर्ज हो चुका है. उन पर 2024 के छात्र आंदोलनों को कुचलने के आरोप हैं जिसमें 1400 से अधिक मौतें हुईं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नई सरकार जिसने अब तक खुद को लोकतांत्रिक बताया है न तो इस केस पर कोई पारदर्शिता दिखा रही है और न ही शेख हसीना के विरोध में हुई कार्रवाइयों की निष्पक्ष जांच की बात कर रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में यह बदलाव किसी सुधार की दिशा में नहीं बल्कि आइडेंटिटी वाइपआउट की रणनीति की तरह लग रहा है. नई सरकार न सिर्फ पुराने शासन के प्रतीकों को हटाने में लगी है, बल्कि अपने धार्मिक और वैचारिक एजेंडे को 'राष्ट्रीय गौरव' के नाम पर थोप रही है. बांग्लादेश कभी भी तालिबान जैसा कट्टरपंथी देश नहीं रहा. लेकिन आज जो बदलाव वहां की नीतियों, प्रतीकों और सरकार के कामकाज की शैली में देखने को मिल रहा है, वह उस ओर इशारा जरूर कर रहा है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमाआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717